www.tamsasanket.com
वर्ष: 05 || अंक 323 || लखनऊ
गुरुवार
26 फ़रवरी 2026 | पृष्ठ: 04 || मूल्य: ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित

मौसम
सूर्योदय: 06:33
सूर्यास्त: 06:05
अधिकतम: 29:00
न्यूनतम: 14:00

विशेष समाचार | बच्चों पर ज्यादा दबाव और... >> पेज 02 | पंकज चौधरी को बायोडेटा... >> पेज 04 | दीपिका कक्कड़ के 13 एमएम...

इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पत्नी के साथ एयरपोर्ट पर रिसीव किया

पीएम मोदी 9 साल बाद इजराइल पहुंचे

- बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ही नेतन्याहू और मोदी ने की प्राइवेट बातचीत।
- नेतन्याहू ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी को नमस्ते किया। साथ ही दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले भी लगाया।

भारत-इजराइल के बीच ड्रोन डील संभव

PM मोदी कल इजराइली प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान भारत और इजराइल के बीच ड्रोन की खरीद और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग समेत कई बड़े रक्षा समझौतों पर सहमति बन सकती है। फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक 2026 में दोनों देशों के बीच 8.6 अरब डॉलर का रक्षा समझौता संभव है। इसमें प्रिसीजन गाइडेड बम और मिसाइल सिस्टम के साथ एडवांस ड्रोन भी शामिल हो सकते हैं।

इजराइल की विशेष दूत बोलीं- अहम समय पर अहम दौरा

इजराइल की विशेष दूत फ्लेर हसन-नाहूम ने पीएम मोदी के दौरे को "अहम समय पर अहम दौरा" बताया है। तेल अवीव में उन्होंने कहा कि हालिया युद्ध के बाद भारत इजराइल का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार बन सकता है। उन्होंने भारत-इजराइल के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर खुशी जताई और कहा कि इससे आर्थिक रिश्ते और मजबूत होंगे। हसन-नाहूम के मुताबिक अगर भारत और इजराइल साथ आते हैं, तो वे AI के भविष्य को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश भविष्य की तकनीक को जिम्मेदार साझेदारी में आगे बढ़ा सकते हैं।

तमसा संकेत, एजेंसी

तेल अवीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के इजराइल दौरे पर पहुंचे हैं। इजराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर मोदी को रिसीव किया। इस दौरान राष्ट्रगान के साथ पीएम का स्वागत किया गया। PM मोदी और नेतन्याहू ने राजधानी तेल अवीव में प्राइवेट बातचीत भी की। मोदी 9 साल बाद इजराइल पहुंचे हैं। इससे पहले वे जुलाई 2017 में गए थे। मोदी आज इजराइल की संसद को भी संबोधित करेंगे। वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा वे भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का दौरा करेंगे। मोदी के इस दौरे पर भारत और इजराइल के हथियारों से जुड़ी डील पर बातचीत की संभावना है। इनमें ड्रोन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। इजराइली अखबार, द जेरूसलम पोस्ट ने PM मोदी के दौरे पर उनके स्वागत के लिए एक खास फ्रंट पेज छापा। फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ हिंदी में लिखा 'नमस्ते' नजर आ रहा है। वहीं उसके बगल में हिब्रू भाषा में भी 'शालोम' लिखा है, जिसका मतलब हेलो या नमस्ते है। इसका दूसरा अर्थ शांति भी होता है।सोमवार को समिति की बैठक में कुछ सांसदों ने सवाल उठाया कि जब भारत ने अपने नागरिकों को संभावित अमेरिकी हमले के खतरे के कारण ईरान छोड़ने की सलाह दी है।

मोदी के भाषण का बहिष्कार कर सकता है इजराइली विपक्ष

इजराइली संसद में होने वाला मोदी का भाषण घरेलू राजनीति के विवाद में घिर गया है। इजराइल का विपक्ष बुधवार को संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार करने की योजना बना रहा है। विवाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आइजैक अमीत को आमंत्रित न किए जाने को लेकर है। इजराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संसद स्पीकर अमीर ओहाना ने विशेष सत्र में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आमंत्रित नहीं किया है। परंपरा के मुताबिक ऐसे औपचारिक सत्रों में चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तेज हो गया है।

प्रवासी भारतीय महिला बोलीं- मोदी से मिलने को उत्साहित
पीएम मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीय यानी इंडो-इजराइली समुदाय में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। तेल अवीव में समुदाय की सदस्य ईवा ने कहा कि वे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, "हम आज भी भारत में निभाई जाने वाली परंपराओं का पालन करते हैं। हम भारत से बहुत प्यार करते हैं।" ईवा ने आगे कहा, "मैं पीएम मोदी से कहूंगी कि वे शानदार काम कर रहे हैं। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं।"

इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के एक्सपर्ट्स अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इनमें गुड्स एंड सर्विसेज का व्यापार, रूल्स ऑफ ओरिजन, हेल्थ और पौधों से जुड़े नियम, व्यापार में आने वाली तकनीकी रुकावटें, कस्टम प्रोसेस, व्यापार को आसान बनाने के उपाय और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे मुद्दे शामिल हैं।

प्रवासी भारतीय महिला बोलीं- मोदी से मिलने को उत्साहित

पीएम मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीय यानी इंडो-इजराइली समुदाय में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। तेल अवीव में समुदाय की सदस्य ईवा ने कहा कि वे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, "हम आज भी भारत में निभाई जाने वाली परंपराओं का पालन करते हैं। हम भारत से बहुत प्यार करते हैं।" ईवा ने आगे कहा, "मैं पीएम मोदी से कहूंगी कि वे शानदार काम कर रहे हैं। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं।"

मणिपुर की दृष्टिबाधित गायिका मोदी के सामने परफॉर्मेंस देंगी

तेल अवीव में मणिपुर की दृष्टिबाधित गायिका दीना सेमटे प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्मेंस देंगी। उन्होंने इसे अपने जीवन का बेहद खास पल बताया। उन्होंने कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि मैं पीएम मोदी के सामने प्रस्तुति दे रही हूं। संगीत सबको जोड़ता है। यह मेरे लिए बहुत विशेष है।"

'ज्यूडीशियल करप्शन' चैप्टर वाली एनसीईआरटी किताब की बिक्री पर रोक

सीजेआई ने कहा था- न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत किसी को नहीं

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की आपत्ति के बाद 'ज्यूडीशियल करप्शन' चैप्टर वाली NCERT किताब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। NCERT के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI से इसकी पुष्टि की। वहीं न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि NCERT किताब से विवादित हिस्सा हटाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, NCERT ने चैप्टर का सुझाव देने वाले एक्सपर्ट्स और इसे मंजूरी देने वाले अधिकारियों की इंटरनल मीटिंग बुलाई है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाया था। सिब्बल ने CJI सूर्यकांत, जस्टिस विपुल एम पंचोली और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच को बताया कि क्लास 8 के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है।

>> (शेष पेज 04 पर)

> इसपर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा- दुनिया में किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह एक सोची-समझी और गहरी साजिश लगती है। मुझे पता है इससे कैसे निपटना है।मैं यह केस खुद हैंडल करूंगा। हम इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहते।

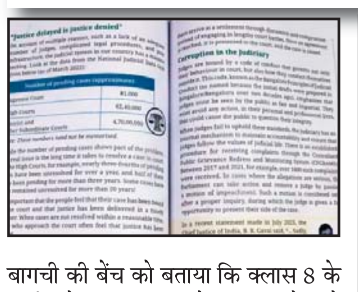

एनसीईआरटी की नई सोशल साइंस टेक्स्टबुक में चैप्टर था

NCERT ने 23 फरवरी को क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस की नई टेक्स्टबुक जारी की थी। ये किताब एकेडमिक सेशन 2026-27 से स्कूलों में पढ़ाई जानी थी। किताब का नाम 'एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2' है। इसमें 'द रोल ऑफ द ज्यूडीशियरी इन अवर सोसायटी' चैप्टर के अंदर 'करप्शन इन द ज्यूडिशियरी' का टॉपिक जोड़ा गया है।

एससी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी राहत

ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर लगाई रोक

तमसा संकेत, एजेंसी

नयी दिल्ली/रांची। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने सोरेन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। याचिका में सोरेन ने मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था। शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में सोरेन ने ईडी द्वारा उन्हें बार बार समन जारी किए जाने को भी चुनौती दी थी। सोरेन ने अपनी याचिका में झारखंड उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। ईडी द्वारा दायर एक मामले में एक विशेष सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत द्वारा सोरेन के खिलाफ संज्ञान लिया था।

फास्ट न्यूज

पहचान सत्यापन में एडमिट कार्ड अकेले मान्य नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान 10वीं या माध्यमिक परीक्षा का एडमिट कार्ड अकेले पहचान के रूप में मान्य नहीं होगा। इसे सिर्फ सहायक (पूरक) दस्तावेज माना जाएगा। एडमिट कार्ड तभी मान्य होगा जब उसके साथ मार्कशीट भी दी जाए। सीनीयर एडवोकेट डीएस नायडू ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला उठाते हुए पूछा था।

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तीन दिन से बर्फबारी जारी

नई दिल्ली/भोपाल/देहरादून/। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पंचाचूली समेत कई क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। यहां ऊंचाई वाले इलाकों में तीन दिन से बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक, 27 और 28 फरवरी से मौसम का मिजाज बदलेगा और पहाड़ी जिलों में बारिश होगी। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, बैतूल और सीहोर समेत 20 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी-बारिश का दौर रहा। कुछ में ओले भी गिरे। इस वजह से गेहूं-चने की फसलों पर असर पड़ा। मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन मार्च की शुरुआत में बारिश होने का अनुमान है।

बॉयफ्रेंड के सामने 7 लोगों ने महिला का रेप किया

गुवाहाटी। असम के कछार जिले के सिलचर शहर के पास एक 28 साल की महिला का उसके बॉयफ्रेंड के सामने 7 लोगों ने गैंगरेप किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में शिकायत 19 फरवरी को दर्ज कराई गई थी। मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि रेप के बाद एक आरोपी ने महिला से 10 हजार रुपए उसके खाते में ट्रांसफर कराए।

ओडिशा माइनिंग अफसर के घर से 4.27 करोड़ नकद मिले

नोट गिनने की मशीनें लाना पड़ीं, 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था

छापेमारी

तमसा संकेत, एजेंसी

कटक। ओडिशा विजिलेंस ने बुधवार को कटक सर्किल के डिप्टी डायरेक्ट (माइंस) देबब्रत मोहंती के घर से 4.27 करोड़ रुपए नकद जब्त किए। मोहंती को लाइसेंसी कोयला व्यापारी से 30 हजार की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आरोप है कि वह कोयला डिपो को बिना रुकावट चलाने और काम आसान करने के बदले रिश्वत ले रहा था। यह ट्रैप ऑपरेशन ओडिशा विजिलेंस ने रिश्वत मांगने की शिकायत मिलने के बाद किया था गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस की टीमों ने मोहंती और उनके करीबियों के कई ठिकानों पर छापे मारे। विभाग ने मठासाही में मोहंती के पैतृक घर और भुवनेश्वर के पाटिया इलाके वाले फ्लैट पर छापा मारा। भुवनेश्वर वाले फ्लैट से सूटकेस, ट्रॉली बैग और अलमारियों में नोटों के ढेर मिले। इसके अलावा, उसके ऑफिस से 1.20 लाख नकद भी बरामद हुए। नोटों की गिनती के लिए करेंसी काउंटिंग मशीनें लाई गईं। विजिलेंस के भुवनेश्वर डिवीजन के एसपी सरोज कुमार समल ने बताया कि अब तक 4.27 करोड़ की गिनती हो चुकी है। जांच में सामने आया है कि मोहंती के पास भुवनेश्वर में दो मंजिला मकान है।

>> (शेष पेज 04 पर)

यूपी में जितनी चुनौतियां, उतनी संभावनाएं : योगी

11 हजार करोड़ के एमओयू पर हुए साइन

मुलाकात

योगी पहली बार जापान पहुंचे, बच्ची ने तिलक लगाया

तमसा संकेत, एजेंसी

टोक्यो। CM योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर जापान पहुंच गए हैं। योगी का यह पहला जापान दौरा है। वहां एक बच्ची ने तिलक लगाकर योगी का स्वागत किया। योगी ने टोक्यो में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नया उत्तर प्रदेश अब दंगा और अंधकार नहीं, बल्कि विकास, विरासत और उत्सवों की पहचान बन चुका है। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जो कई देशों की कुल आबादी से भी अधिक है। पूरे वर्ष में लगभग 156 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों काशी, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन और बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा की। योगी ने कहा, "हमारे बारे में पूछा जाता है कि हम सनातनी क्यों हैं? क्योंकि 'कृते च प्रति कर्तव्यं' अर्थात किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो उसके प्रति आभार व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है।"

> *मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी तीर्थस्थलों के विकास के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलें और धार्मिक पर्यटन को वैश्विक पहचान मिले। उन्होंने कहा, "कोई भी समाज अपनी विरासत पर गर्व करके ही आगे बढ़ सकता है। विरासत पर गर्व अपने पूर्वजों और महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम है।"*

>> (शेष पेज 04 पर)

"अब यूपी दंगा-कर्फ्यू नहीं, उत्सवों की पहचान"

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में दंगा और कर्फ्यू की खबरें नहीं आतीं, बल्कि विकास और उत्सवों की चर्चा होती है। अयोध्या में दीपोत्सव, वाराणसी में देव दीपावली, मथुरा-वृंदावन में रंगोत्सव और बरसाना की लट्ठमार होली जैसे आयोजन प्रदेश की नई पहचान बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि कल बरसाना में करीब 5 लाख श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे, जबकि आज नंदगांव में उससे भी अधिक लोगों की उपस्थिति है। उन्होंने कहा कि यह बदले हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जहां शांति, सुरक्षा और सांस्कृतिक आस्था एक साथ आगे बढ़ रही है।

आरोप : बच्चों से कुकर्म की पुष्टि हुई ■ शंकराचार्य का जवाब- बटुक हमारे पास नहीं थे

यूपी के डिप्टी सीएम साजिश कर रहे : आशुतोष महाराज

तमसा संकेत, एजेंसी

वाराणसी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज ने बुधवार शाम प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, अविमुक्तेश्वरानंद ने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और वाराणसी के मठ-आश्रमों में बटुकों का यौन शोषण किया है। सारे सबूत हमारे पास हैं। मेडिकल में बटुकों से कुकर्म की पुष्टि हो गई है। जल्द ही मामले में न्याय होगा। आशुतोष महाराज ने यूपी के डिप्टी CM पर प्रयागराज माघ मेले में साजिश रचने का आरोप लगाया। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया। आशुतोष ने कहा, अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में कई सपा नेता और कांग्रेसी आते-जाते थे। उनके नाम सामने आए हैं। वह बटुकों के कुकर्म में तो शामिल नहीं थे? इसकी जांच हो रही है। माघ मेला साजिश में यूपी के डिप्टी CM शामिल हैं। डिप्टी CM ने कहा था कि अभी धरना दो, जब हम आएं, तब खत्म करना। इसके बाद शंकराचार्य ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेडिकल में यौन शोषण की पुष्टि पर शंकराचार्य ने कहा, वह बच्चा हमारे पास आया ही नहीं तो कैसे हो सकता है।

>> (शेष पेज 04 पर)

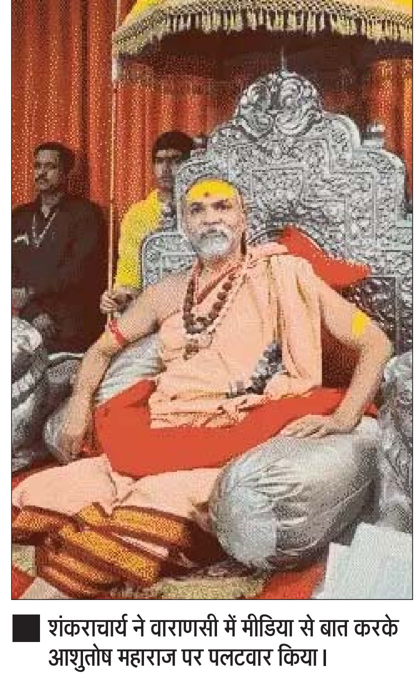

■ शंकराचार्य ने वाराणसी में मीडिया से बात करके आशुतोष महाराज पर पलटवार किया।

अरुणाचल की महिलाओं पर नस्लीय कमेंट करने वाले पति-पत्नी गिरफ्तार

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं पर नस्लीय टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी रूबी जैन और उसके पति हर्ष सिंह को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को SC/ST Act के तहत गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने कपल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इससे पहले मंगलवार को हर्ष सिंह ने न्यूज एजेंसी से कहा कि हम शर्मिंदा हैं। ये सब कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। हर्ष ने कहा कि मामले में हम दिल्ली पुलिस का पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उनका ऑफिस पहले दिन से ही पीड़ितों और दिल्ली पुलिस के लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिजिजू ने कहा कि मामले में गिरफ्तारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में नॉर्थईस्ट के लोगों के खिलाफ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार को अधिकारी गंभीरता से लेते हैं।

इंडिगो फ्लाइट में 200 से ज्यादा यात्री 4 घंटे फंसे

पायलट भी उतरा, चेन्नई से सिंगापुर जाना था, पैसेंजर्स बोले- एसी बंद

समस्या

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। चेन्नई से सिंगापुर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 1025 24 फरवरी को तकनीकी कारणों से करीब 5 घंटे लेट हो गई। इससे विमान में बैठे 200 से ज्यादा यात्री रनवे पर फंसे रहे। उन्होंने जानकारी के अभाव और एयर कंडीशनिंग की समस्या को लेकर भी नाराजगी जताई। घटना का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में यात्री क्रू से टेक-ऑफ में देरी का कारण पूछते दिख रहे हैं। एक यात्री ने आरोप लगाया कि विमान के अंदर एयर कंडीशनिंग बार-बार बंद हो रही है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एक अन्य यात्री ने कहा कि वे सुबह 7 बजे से इंतजार कर रहे हैं।

- एयरपोर्ट के पार्किंग में कई यात्री फ्लाइट के गेट पर क्रू से बहस करते दिखे।
- यात्रियों ने दावा किया कि ड्यूटी खत्म होने के कारण पायलट भी विमान से उतरकर चला गया।

>> (शेष पेज 04 पर)

सम्पादकीय

हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

लंबे समय से विवाद और तनाव के केंद्र में रहे उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे और साथ ही राज्य सरकार की जमीन पर अवैध तरीके से बसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने वहां से हटाने का फैसला करके वही किया, जो न्यायसंगत था। यदि यह मांग मान ली जाती कि अतिक्रमण करके बसे लोगों को वहीं रहने दिया जाए तो इससे न केवल करीब 30 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा वैध हो जाता, बल्कि रेलवे के विस्तार की महत्वाकांक्षी परियोजना पर ग्रहण भी लगता। सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कहा कि अवैध तरीके से बसे लोग यह तय नहीं कर सकते कि रेलवे रेल लाइन विस्तार के लिए अन्य विकल्प चुने, लेकिन इसी के साथ उसने इस जमीन से बेदखल होने वालों के प्रति जो मानवीय दृष्टिकोण अपनाया, उसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगभग पांच हजार परिवारों के जो हजारों लोग रेलवे और उसके पास की राज्य सरकार की जमीनों पर रह रहे हैं, उनमें से पात्र लोगों को पीएम आवास योजना के तहत आवास दिए जाएं। इस फैसले पर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ने पात्र परिवारों को विस्थापन के बाद छह महीने तक प्रति माह 2,000 रुपये भत्ता देने का भी वादा किया। पहली नजर में यह लग सकता है कि एक तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को पुरस्कृत किया जा रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इस कब्जे को लेकर न तो रेलवे समय रहते चेता और न ही उत्तराखंड सरकार। यह एक तथ्य है कि आम तौर पर सरकारी विभाग अपनी जमीनों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे को लेकर उदासीन बने रहते हैं और फिर यकायक अपनी जमीन खाली कराने की सुध लेते हैं। इससे वहां रह रहे लोगों के सामने संकट खड़ा हो जाता है। उनके रहने का ठिकाना छिनने के साथ ही उनकी रोजी-रोटी भी प्रभावित होती है। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले को नजीर न माना जाए और उसने जो मानवीय दृष्टिकोण अपनाया, वह मदद ज्यादा और अधिकार कम है। देश में हजारों एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हैं। इसके लिए कब्जा करने वालों के साथ वे विभाग भी जिम्मेदार हैं, जो अपनी जमीनों पर कब्जे के समय आंखें मूंदे रहते हैं। यदि सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराना है तो वहां दशकों से रह रहे लोगों के पुनर्वास के बारे में कोई ठोस नीति बनानी होगी। ध्यान रहे अपने देश में अपनी ही जमीनों पर बसे लोगों को जब किसी परियोजना के चलते विस्थापित किया गया तो उनमें से भी अनेक का न तो ढंग से पुनर्वास किया गया और न ही उनकी आजीविका की चिंता की गई। निःसंदेह सरकारी अथवा गैर-सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे मुक्त होने चाहिए, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण के साथ।

बच्चों पर ज्यादा दबाव और रोक-टोक के भयंकर परिणाम

“हर बच्चे की एक क्षमता और योग्यता है, उसे उस के अनुसार काम करने दे। जबरदस्ती किसी को सफलता नहीं दिलाई जा सकती, जब तक वो खुद न चाहे। बच्चों को उनका काम करने में मदद करें, वो जो भी करना चाहते हैं, उन्हें करने का मौका दें। आज जब गलाकाट प्रतियोगिता चल रही है, तब हर बच्चे से बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

वर्तमान हालात बच्चों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हैं. हमारे लिए इसे समझना बेहद मुश्किल है। आज से 30-40 साल पहले बच्चे का अच्छे नंबर लेकर पास होना उसके उज्ज्वल भविष्य की गारंटी माना जाता था । अब ऐसा नहीं रहा है. जब शत-प्रतिशत अंक आने लगे हैं तो 90 प्रतिशत अंक लाने वाले छात्र भी फेल मान लिए जाते हैं। देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि शत-प्रतिशत अंक लाने वाला छात्र 80-90 प्रतिशत अंक वाले छात्र से बेहतर हो। किसी भी छात्र के अंक उसकी मेहनत या मेधा के प्रतीक नहीं होते, उसके स्वभाव के प्रतीक भी हो सकते हैं। आजकल बच्चों पर मां-बाप का ज्यादा से ज्यादा अंक लाने का दबाव होता है। स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद उन्हें इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का दबाव भी मां-बाप का होता है। आजकल मां-बाप बच्चों से पूछने लगे हैं कि वो क्या करना चाहता है. फिर उसके अनुसार ही उसे आगे बढ़ने का मौका देते हैं। सच यह है कि ज्यादातर अभिभावक बच्चों के भविष्य का फैसला खुद करना चाहते हैं। उनकी शिक्षा, करियर और विवाह तक सारे फैसले खुद लेना चाहते हैं और अपने फैसलों को बच्चों पर थोपना अपना अधिकार समझते हैं। उनका कहना होता है कि हम मां-बाप हैं. बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं. हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छा जीवन जियें, इसलिए उनका मार्गदर्शन करते हैं। बच्चों का मार्गदर्शन करना हर माता-पिता का अधिकार और कर्तव्य है लेकिन इसकी एक सीमा है। आजकल बच्चे अच्छी शिक्षा के बावजूद मनपसंद रोजगार हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जब उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो वो विवाह से भागने लगते हैं। बुरी संगत में पड़कर व्यसनों का शिकार बन जाते हैं। ऐसे हालातों में उनके परिजनों के लिए उनको समझना मुश्किल हो जाता है। इन बच्चों का धीरे-धीरे व्यवहार बदलने लगता है। हम बच्चों को यह दोष देने लगते हैं कि ये बदल गया है लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते कि क्यों ऐसा हो रहा है। बच्चों के बदलते व्यवहार को समझे बिना, उनके ऊपर तरह-तरह से दबाव बनाया जाने लगता है। इस खींचतानी का कई बार बड़ा बुरा परिणाम निकलता है। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनमें पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। लखनऊ में रिश्तों को शर्मसार करने की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक 21 वर्षीय बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। विडम्बना यह है कि ये हत्या उसने अचानक आवेश में आकर नहीं की है बल्कि सोच-समझकर इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया है । उसने इसके लिए पूरी योजना बनाई, फिर हत्या की और उसके बाद उसने पिता के शव के टुकड़े-टुकड़े करके जंगल में फेंक दिये। इसके अलावा उसने पिता के शव का एक हिस्सा घर में नीले ड्रम में छुपा दिया। वो ये हत्या करने के बाद सामान्य बना रहा और खुद थाने जाकर पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया है. आरोपी के पिता मानवेन्द्र सिंह एक पैथोलॉजी लैब के मालिक थे. इसके अलावा भी उनके दूसरे व्यवसाय थे। वो अपने बेटे और बेटी के साथ रहते थे, उनकी पत्नी का नौ साल पहले निधन हो चुका था। पिता चाहते थे कि बेटा नीट क्लियर करके डॉक्टर बन जाये लेकिन बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। उसने कई बार पिता को मना किया था, लेकिन पिता उस पर डॉक्टर बनने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। उसने पिता के दबाव से परेशान होकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। एक दूसरी ऐसी ही शर्मनाक घटना मुज्जफरनगर में सामने आई है। इसमें दो बहनों ने अपने पिता की रोक-टोक से परेशान होकर उसकी नृशंस हत्या कर दी। उन्होंने परिवार के सदस्यों को नींद की गोलियां देकर सुला दिया और इसके बाद पिता को चाकू से गोदकर मार दिया। बड़ी बहन की उम्र 32 साल है और छोटी बहन 16 साल की है, दोनों बहनों ने पूरी योजना बनाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। ये हत्या भी अचानक आवेश में आकर की गई हत्या नहीं है बल्कि योजनाबद्ध तरीके से की गई हत्या है। दोनों बहनों का पहला गुस्सा तो इस बात को लेकर था कि उनके साथ बेटी होने के कारण भेदभाव किया जाता है। बेटियों के साथ भेदभाव हमारे समाज के लिए बहुत ही सामान्य बात है लेकिन दोनों बहनें इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा पिता बड़ी बेटी के अविवाहित होने पर ताना मारते थे। उनको कुँवारी बेटी का घर बैठना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये पता नहीं है कि बेटी का विवाह क्यों नहीं हो रहा था लेकिन इसके लिए वो अकेली दोषी नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा हो। एक तो विवाह नहीं हो रहा था, उस पर पिता के तानों ने उनको गुस्से से भर दिया और उसने अपने पिता का ही कत्ल कर दिया। इसके अलावा कितनी ही घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें बच्चे अपने ही परिजनों की हत्या कर रहे हैं। बच्चे सिर्फ दूसरों की हत्या ही नहीं कर रहे हैं बल्कि आत्महत्या भी कर रहे हैं। बेटे और बेटियों ने अपने पिता को इतनी क्रूरता से क्यों और कैसे मारा, ये एक अलग मुद्दा है। मेरा मुद्दा यह है कि ऐसे हालात क्यों और कैसे पैदा हो गए कि वो अपने ही पिता के हत्यारे बन गए। अगर ये बच्चे आत्महत्या कर लेते तो क्या घटना इतनी ही गंभीर नहीं होती। बच्चों ने हत्या की या आत्महत्या, दोनों ही घटनाएं चिंता पैदा करने वाली हैं। सवाल यह है कि हम अपने बच्चों के लिए सारे फैसले लेना इतना सामान्य क्यों समझते हैं। उनको समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनेगा, ये हम कैसे तय कर सकते हैं। बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है तो क्या हम उसे ताने देना शुरु कर दे। उनके जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश हम क्यों करते हैं। इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि हर मां-बाप अपने बच्चे का भला चाहते हैं लेकिन सब कुछ वो तय नहीं कर सकते। बच्चों की समझ और विचार को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो कितने भी छोटे या बड़े क्यों न हों। जब मेरा बेटा पांचवी कक्षा में पढ़ता था तो मैंने उसका स्कूल बदलवा दिया। वास्तव में दूसरा स्कूल कई मामलों से पुराने स्कूल से बेहतर था, मेरी नजर में मेरा फैसला बहुत सही था जो उसके बेहतर भविष्य के लिए था। मेरा बेटा एक माह तक नए स्कूल में गया और धीरे-धीरे उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया। उसने खेलना कम कर दिया, कम बोलने लगा और चुप-चुप रहने लगा। मैं जब उसे स्कूल के गेट पर छोड़कर आता तो वो मेरी आँखों से ओझल होने से पहले मुझे मुड़-मुड़ कर देखता था। उसके चेहरे पर एक स्थायी उदासी घर कर गयी थी। मैं और मेरी पत्नी उसके बदलते स्वभाव से परेशान हो गए। एक दिन हमने प्यार से बैठाकर शांति से पूछा कि बेटा नया स्कूल कैसा है। उसने बताया कि उसका स्कूल में दिल नहीं लगता. उसे स्कूल पसंद नहीं है, कोई उससे दोस्ती नहीं कर रहा। हमें अहसास हो गया कि सात साल तक पुराने स्कूल में रहने का आदी हो गया है, इसलिए उसका दिल नहीं लग रहा है। तब हमने उसे वापस पुराने स्कूल भेजने का फैसला किया जबकि इसका मुझे बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। हो सकता है कि कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया हो, लेकिन बच्चे की उदासी और बदलते व्यवहार के कारण हमने उसे पुराने स्कूल में भेज दिया । जब मैं उसके पुराने स्कूल में दाखिल करके आया तो उसकी पूरी क्लास में उसके वापस आने की खुशी मनाई गई। कुछ दिन में ही मुझे लगा कि मेरा बेटा कहीं खो गया था।

राजेश कुमार पासी

पैक्स सिलिका जैसे...

ललित गर्ग

पैक्स सिलिका में भारत का होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि

इक्कीसवीं सदी का यह दौर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और तकनीकी आपूर्ति श्रृंकखलाओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धा का दौर बन चुका है। ऐसे समय में भारत द्वारा एआई शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन और उसके तुरंत बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले समूह पैक्स सिलिका से औपचारिक रूप से जुड़ना केवल एक कूटनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी और रणनीतिक कदम है। यह उस नए भारत की घोषणा है जो तकनीकी शक्ति, नैतिक दृष्टि और वैश्विक संतुलन-तीनों को साथ लेकर चलने का सामर्थ्य अर्जित कर रहा है। एआई समिट के माध्यम से भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह अब केवल तकनीक का उपभोक्ता राष्ट्र नहीं, बल्कि निर्माता और मार्गदर्शक की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। दुनिया की तीसरी बड़ी एआई शक्ति बनने की दिशा में यह एक ठोस चरणन्यास है। दुर्लभ खनिजों और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का लगभग 90 प्रतिशत वर्चस्व पिछले कुछ वर्षों से वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। कंप्यूटर चिप से लेकर रक्षा प्रणालियों और अंतरिक्ष तकनीक तक, हर क्षेत्र इन संसाधनों पर निर्भर है। इस पृष्ठभूमि में पैक्स सिलिका जैसे मंच की परिकल्पना एक संतुलित, विश्वसनीय और बहु-धुरवीय तकनीकी ढांचे के रूप में की गई है। भारत का इस समूह में शामिल होना केवल प्रतीकात्मक

कदम नहीं, बल्कि रणनीतिक और अनिवार्य निर्णय है। भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, विशाल युवा प्रतिभा और उभरता हुआ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इस गठबंधन को नई मजबूती प्रदान करेगा। यह पहल किसी के विरुद्ध आक्रामकता नहीं, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में संतुलन और विविधता स्थापित करने का प्रयास है। जब शक्ति का केंद्रीकरण टूटता है और साझेदारी का विस्तार होता है, तभी विश्व व्यवस्था स्थिर और संतुलित बनती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत ने तकनीक को शासन और विकास के केंद्र में स्थापित किया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों ने एक मजबूत आधार तैयार किया है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुका है। आधार, यूपीआई और डिजिटल सेवाओं ने करोड़ों लोगों को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ा है। इसी आधार पर एआई और चिप निर्माण के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की सक्रियता और वैश्विक मंचों पर भारत की प्रभावी उपस्थिति ने देश को एक विश्वसनीय तकनीकी साझेदार के रूप में स्थापित किया है। उनका दृष्टिकोण केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता को वैश्विक सहयोग के साथ जोड़ने का है। भारत में चिप डिजाइन, निर्माण और एआई अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बड़े निवेश आकर्षित किए जा रहे हैं। वैश्विक कंपनियाँ भारत को स्थिर लोकतंत्र, कुशल मानव संसाधन और दीर्घकालिक नीति स्थिरता वाले देश के रूप में देख रही हैं। पैक्स सिलिका जैसे अंतरराष्ट्रीय ढांचे का हिस्सा बनने से भारत को तकनीकी सहयोग, संयुक्त अनुसंधान, पूंजी निवेश और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण में व्यापक लाभ मिलेगा। इससे न केवल चीन पर निर्भरता कम होगी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता भी सुदृढ़ होगी। यह भागीदारी भारत को अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देशों जैसी प्रमुख तकनीकी शक्तियों के साथ और अधिक निकटता से जोड़ेगी, जिससे वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में भारत की प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ेगी। भारत की विशेषता केवल तकनीकी क्षमता नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टि भी है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना से प्रेरित भारत एआई को मानव-केंद्रित विकास का माध्यम बनाना चाहता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से व्यापक जनकल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है। यदि तकनीक कुछ शक्तियों के हाथों में सिमट जाए तो असंतुलन बढ़ता है, किंतु जब लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र इसका नेतृत्व करते हैं तो यह वैश्विक कल्याण का साधन बन सकती है। भारत का प्रयास है कि एआई के नैतिक मानदंड सार्वभौमिक हों और तकनीक का उपयोग हथियार के रूप में नहीं, बल्कि मानव प्रगति के साधन के रूप में हो। भारत की दृष्टि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल तकनीकी प्रगति का उपकरण नहीं, बल्कि मानवीय चेतना के विस्तार का माध्यम है। जिस देश ने विश्व को “वसुधैव कुटुम्बकम्” का मंत्र दिया, जिसने करुणा, अहिंसा और सह-अस्तित्व की परंपरा को जीवन-मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित किया, वह एआई को भी केवल बाज़ार और प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा में नहीं, बल्कि मानव कल्याण और वैश्विक संतुलन के संदर्भ में देखता है। भारत की सभ्यता-चेतना, जो महात्मा गांधी की अहिंसा और गौतम बुद्ध की करुणा से अनुप्राणित है, तकनीकी विकास को नैतिक अनुशासन से जोड़ने की प्रेरणा देती है।

इसमें उनके...

00000000

सिंगर बनना चाहती थीं एक्ट्रेस रूही सिंह

'मस्ती 4' (2025) फेम एक्ट्रेस रूही सिंह के नाम से एक डबल मीनिंग व्हाट्सऐप चैट्स सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से पिछले दिनों वह काफी चर्चाओं में रहीं। रूही साफ कर चुकी हैं कि ये चैट्स उनकी नहीं हैं और इस सबंध में उन्होंने केस भी दर्ज करवाया है। हिंदी फिल्मों और टेलीविजन की एक्ट्रेस रूही सिंह एक मॉडल और ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर हैं। 'फेमिना मिस इंडिया ईस्ट 2011' प्रतियोगिता में भाग लेकर रूही सिंह फर्स्ट रनर अप बनीं। उसके बाद उसी साल उन्हें चीन में आयोजित 'मिस मॉडल ऑफ़ द वर्ल्ड 2011' प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया जहाँ वह टॉप 36 क्वार्टर फाइनलिस्ट में शामिल हुईं। 2012 में उन्होंने 'फेमिना मिस इंडिया' में भाग लिया और टॉप 10 में जगह बनाई। उसी साल, मियामी में आयोजित 'मिस यूनाइटेड नेशंस 2012' में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन रूही को असल सफलता साल 2014 में उस वक्त मिली, जब उन्हें फेमिना मिस इंडिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। उसी साल उन्होंने 'मिस यूनिवर्सल पीस एंड ह्यूमैनिटी 2014' का खिताब जीता। द टाइम्स ऑफ़ इंडिया व्दारा रूही सिंह को भारत की 'टॉप 25 सबसे डिज़ायरेबल वूमेन' में से एक (2014) नामित किया गया था। इसके बाद 'टाइम्स मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन 2020' में वह नवे नंबर पर रहीं। 12 अक्टूबर 1995 को जयपुर में पैदा हुई रूही सिंह का सपना एक सिंगर बनने का था लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। तभी तो साल 2011 में उन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा और उसके बाद उनकी सारी प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल गईं। रूही सिंह कनाडाई एमी-नॉमिनेटेड डॉक्यूमेंट्री 'द वर्ल्ड बिफोर हर' (2012) में नज़र आ चुकी हैं। इसमें उनके काम से प्रभावित होकर बॉलीवुड फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने उन्हें अपनी फिल्म 'कैलेंडर गर्ल्स' (2015) की पांच लीडिंग लेडीज़ में से एक के तौर पर साइन किया। इस तरह 25 सितंबर 2015 को रिलीज़ फिल्म 'कैलेंडर गर्ल्स' के जरिए रूही सिंह को अपने सिनेमाई सफर की शुरुआत करने का अवसर मिला। इसके बाद उन्हें फिल्म 'इश्क फॉर एवर' में देखा गया। रूही सिंह को एम एक्स प्लेयर की सीरीज 'चक्रव्यूह' (2021) और 'रनअवे लुगाई' (2021) की भूमिकाओं के लिए जबर्दस्त लोकप्रियता मिली। 'चक्रव्यूह' (2021) में उनका रोल कई लेयर्स वाला था और उसमें जिस तरह से उन्होंने इंटेंसिटी बनाए रखी वह अपने आप में वाकई लाजवाब था। 'रनअवे लुगाई' (2021) एक दिलचस्प और मनोरंजक ड्रामा सीरीज़ साबित हुई। इसमें एक छोटे शहर की भागी हुई बोल्ड दुल्हन बुलबुल के किरदार के लिए न सिर्फ़ क्रिटिकली सराहा गया बल्कि दर्शकों को भी यह सीरीज बेहद पसंद आई।

नकली-घटिया सामग्री का बढ़ता बाजार

होली निकट आते ही देश भर से ऐसे समाचार आने का सिलसिला कायम हो गया है कि नकली खोया, पनीर या फिर मिलावटी मिठाइयां बरामद। बीते सप्ताह आगरा की एक खबर के अनुसार राजस्थान से लाया गया 1,320 किलो मिलावटी खोया बरामद किया गया। कानपुर से आई एक खबर यह कहती है कि होली और रमजान के पहले 50 लाख रुपये मूल्य के दस हजार किलो पुराने और खराब हो चुके खजूर के पैकेटों पर नए लेबल चिपकाकर उन्हें बाजार में खपाने की तैयारी थी। इसी दिन की एक अन्य खबर के मुताबिक कानपुर में ही छह सौ किलो मिलावटी खोया पकड़ा गया। इसके अलावा लगभग दो लाख रुपये से अधिक मूल्य की कटी हुई सुपारी भी जब्त की गई, जिसे मिलावटी पाए जाने पर नष्ट किया गया। बीते दिनों लखनऊ से आई खबर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसमें करीब 13 क्विंटल सड़े-गले और मानव उपयोग के लिए असुरक्षित खजूर नष्ट कराए गए। इसी अभियान के तहत दो हजार किलो हल्दी, 20 हजार किलो सुपारी जब्त की गई, क्योंकि उसके खराब होने का संदेह था। सहारनपुर की एक खबर के अनुसार खाद्य विभाग ने रामपुर मनिहारान कस्बे में करीब साढ़े छह क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद किया। गत दिनों ही भीलवाड़ा में एक कोल्ड स्टोरेज से बड़ी मात्रा में संदिग्ध मिलावटी मसाले जब्त किए गए। इनमें 23 सौ किलो लाल मिर्च पाउडर और 17 सौ किलो साबुत धनिया को मिलावटी होने के संदेह में जब्त किया गया। इसी माह गुजरात के साबरकांठा में डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, यूरिया आदि का इस्तेमाल करके नकली दूध और छाछ बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। यह फैक्ट्री पिछले पांच सालों से चल रही थी। बीते दिनों आंध्र के एक कस्बे में मिलावटी-जहरीला दूध पीने से पांच लोगों की मौत हो गई। यदि बीते 15-20 दिनों की ही देश भर से आई ऐसी खबरों का संज्ञान लिया जाए तो उनका उल्लेख करने के लिए यह पूरा पेज या फिर समाचार पत्र भी कम पड़ सकता है।

राजीव सचान

जरा हटके

सुप्रीम कोर्ट ने...

अशोक भाटिया

यूजीसी के समता विनियम की गंभीर समीक्षा हो

विगत दिनों आया यूजीसी का समता संवर्धन विनियम गंभीर समीक्षा की मांग करता है क्योंकि जब से यह आया है, तभी से चिंता स्वरूप इसके विरोध और समर्थन का मुद्दा अब राजनीतिक रंग ले रहा है। देश के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों व अन्य स्थानों पर भी धरने- प्रदर्शन जारी हैं। विगत दिनों विनियम के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे वामपंथी संगठन के छात्रों ने सवाल पूछने पर महिला यूट्यूबर रुचि तिवारी को पीट दिया। हाल ही में जेएनयू में छात्रों के दो ग्रुपों में जमकर झगड़ा हुआ है। एक समाचार यह भी है कि मध्यप्रदेश की छात्रा सोनाली प्रजापति ने मंत्री विजय शाह से यह प्रश्न पूछा कि पढ़ाई में जातिगत भेदभाव क्यों किया जा रहा है? शिक्षा के लिए जातिगत नहीं, आर्थिक आधार पर सरकारी सुविधाएं दी जानी चाहिए क्योंकि हर वर्ग में लोग पिछड़े हैं। क्या उपर्युक्त दोनों समाचार गंभीर नहीं हैं? ध्यातव्य है कि 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026 प्रकाशित किया। विनियम के उद्देश्य में लिखा है कि- धर्म, नस्ल, जाति, लिंग,जन्म स्थान या दिव्यंगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना है। विनियम के प्रकाशित होते ही इसके देशव्यापी विरोध के समाचार आने लगे। तदुपरांत कहीं-कहीं से समर्थन के समाचार भी आ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इस मामले में अभी यथास्थिति का आदेश जारी किया है। यहां प्रश्न यह है कि जब विनियम का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता की बात करता है तो क्या उपर्युक्त वर्णित वर्गों के अतिरिक्त सामान्य वर्ग के छात्र इस हितधारक श्रेणी में नहीं हैं? ध्यान रहे शिक्षण संस्थान विद्या के मंदिर हैं जहां सभी विद्यार्थी एकता एवं समानता का पाठ पढ़ते हैं। क्या शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को इस प्रकार के घोषित जाति आधारित वर्गीकरण में बांटना उचित है जबकि शिक्षण संस्थानों में किसी

भी प्रकार की असमानता अथवा भेदभाव के उन्मूलन हेतु पहले से ही प्रावधान हैं। प्रश्न यह भी है कि क्या सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव नहीं होता? यदि होता है तो क्या उनके लिए भी अलग विनियम नहीं होने चाहिए? प्रस्तुत विनियम जिस प्रकार से विभिन्न शब्दों की परिभाषा देता है। समता के संवर्धन का कर्तव्य बताता है। समान अवसर केंद्रों का प्रविधान करता है। समता के संवर्धन हेतु उपाय, घटनाओं के मामले में प्रतिक्रिया, अपील, निगरानी एवं अनुपालन आदि की विस्तृत रूपरेखा बताता है। यह रूपरेखा शिक्षण संस्थानों की सभी के लिए समान की भावना को खंडित करेगी। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के अंतर्गत समता का अधिकार सभी के लिए धर्म,मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करता। क्या शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव के संबंध में संविधान का यह प्रविधान लागू नहीं होता? यदि हां तो फिर अलग से यूजीसी का यह विनियम क्यों बनाया गया है? क्या यह विनियम इससे जुड़े अधिकारियों की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा है? यूजीसी का यह जिम्मा है कि वह देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रयास करे। अधिकाधिक छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर मिले, इसके लिए प्रयास करे। छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की संख्या सुनिश्चित करे। संविधान सम्मत विभिन्न आरक्षित वर्ग के छात्रों के कल्याण हेतु छात्रवृत्तियों आदि का प्रावधान सुनिश्चित करे। आज भी देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भिन्न-भिन्न रूपों में ढांचागत सुविधाओं का नितांत अभाव है। क्या यूजीसी को उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्याय 6 स्पष्ट करता है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक लगातार नामांकन घट रहा है। नामांकन में यह गिरावट सामाजिक- आर्थिक रूप से वंचित समूहों में अधिक है। क्या आर्थिक रूप से वंचित समूह की श्रेणी में सामान्य जातियों के छात्र नहीं आते? इसी प्रकार नीति का अध्याय 14 उच्च शिक्षा में समता और समावेश शीर्षक से स्पष्ट करता है कि विद्यालयी शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समता, समानता और समावेश से जुड़ा दृष्टिकोण एक समान होना चाहिए। क्या यूजीसी द्वारा प्रकाशित यह विनियम सभी की समानता के विरुद्ध नहीं है? नीति में आगे लिखा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ बने सभी नियमों को शक्ति से लागू करना। क्या इस निर्देश के दायरे में अनुसूचित जाति, जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के छात्र नहीं आते? यदि आते हैं तो फिर यूजीसी का यह नया विनियम क्यों? ध्यातव्य है कि यूजीसी का यह नया विनियम एक प्रकार से संविधान सम्मत अधिकारों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को कमजोर सिद्ध करते हुए वैमनस्य पैदा करने का प्रयास है। आज हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जाति,भाषा अथवा क्षेत्रीयता आधारित भेदभाव भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रकृति नहीं है। यह व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के विकास में बाधक है। भारतीय ज्ञान परंपरा,संत परंपरा और महापुरुषों का संदेश स्पष्ट है कि जाति के भेदभाव को मिटाकर ही मानवता के कल्याण का रास्ता बनाया जा सकता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत लगातार समरस समाज हेतु जन जागरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार सबका साथ, सबका विकास हेतु विभिन्न योजनाएं बनाकर पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। फिर अचानक यूजीसी इस प्रकार के मतभेद खड़े करने वाला विनियम लेकर क्यों आया? क्या यूजीसी की यह तत्परता चिंताजनक नहीं है? शिक्षण संस्थान वे केंद्र हैं जो समाज को मार्गदर्शन देते हैं। शिक्षण संस्थानों में विभिन्न रूपों में प्रवेश हेतु संविधान सम्मत आरक्षण के प्रविधान हैं। तदुपरांत शिक्षण संस्थानों में पहुंचा किसी भी जाति, संप्रदाय अथवा क्षेत्र का विद्यार्थी केवल विद्यार्थी माना जाए। वहां उसके साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव अथवा शोषण के मामले को गंभीरता से हल किया जाना चाहिए।

विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी

12 टीमें खेलेंगी 33 मुकाबले, पाकिस्तान के खिलाफ मैच से शुरू होगा भारत का अभियान

■ न्यूजीलैंड विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप की मौजूदा चैंपियन है। टीम ने 2024 के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 32 रन से हराया था।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। टूर्नामेंट का 10वां संस्करण 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। इस बार प्रतियोगिता में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। ICC का यह कदम महिला क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता ने शेड्यूल जारी होने पर कहा कि यह टूर्नामेंट महिला क्रिकेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि ICC लगातार महिला क्रिकेट में निवेश बढ़ा रहा है, जिसमें भागीदारी बढ़ाना, बेहतर आयोजन, उच्च स्तर का प्रसारण, अधिक पुरस्कार राशि और व्यावसायिक साझेदारियों को मजबूत करना शामिल है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह टूर्नामेंट महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और दुनिया भर में इसकी लोकप्रियता में और वृद्धि करेगा। विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम रही है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अब तक रिकॉर्ड छह बार खिताब अपने नाम किया है, जिससे उसने इस फॉर्मेट में अपनी बादशाहत कायम रखी है। इसके अलावा इंग्लैंड ने 2009 में पहला संस्करण जीतकर इतिहास रचा था, जबकि वेस्टइंडीज ने 2016 में खिताब जीतकर सभी को चौंका दिया था। भारत की टीम भी पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही है और इस बार खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है।

महिला क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक टूर्नामेंट बनने की उम्मीद

ICC विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार 12 टीमों की भागीदारी महिला क्रिकेट के विस्तार का स्पष्ट संकेत है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह टूर्नामेंट न केवल प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा बल्कि नए देशों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देगा।

> टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला 12 जून को मेजबान इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला टूर्नामेंट की शुरुआत के साथ ही रोमांचक प्रतिस्पर्धा का संकेत देगा। इंग्लैंड की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी, जबकि श्रीलंका मजबूत प्रदर्शन कर उलटफेर करने की उम्मीद में मैदान पर उतरेगी।

दो ग्रुप में बांटी गई हैं 12 टीमें

ICC ने सभी 12 टीमों को 6-6 टीमों के दो ग्रुप में विभाजित किया है। प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की अन्य टीमों के खिलाफ मुकाबले खेलेगी। ग्रुप चरण समाप्त होने के बाद दोनों ग्रुप की शीर्ष दो-दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। इसके बाद विजेता टीमें फाइनल में खिताब के लिए भिड़ेंगी। इस नए फॉर्मेट से प्रतियोगिता और अधिक प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है, क्योंकि अधिक टीमों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

भारत-पाकिस्तान मुकाबले से शुरू होगा टीम इंडिया का अभियान

भारत महिला क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला 14 जून को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलेगी। भारत-पाकिस्तान मैच हमेशा से हाई-वोल्टेज मुकाबला माना जाता है और इस मैच पर दुनियाभर के क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें रहेंगी। भारतीय टीम को ग्रुप चरण में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ग्रुप में मौजूदा दिग्गज टीम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के अलावा दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम, बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम और नीदरलैंड महिला क्रिकेट टीम भी शामिल हैं। ऐसे में भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

रहस्यमयी नॉर्थ कोरिया की 'फुटबॉल डिप्लोमेसी'

16 साल बाद एशियन मंच पर वापसी कर रही महिला टीम

सिडनी/प्योंगयोंग, एजेंसी

दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों में शुमार नॉर्थ कोरिया एक बार फिर सुर्खियों में है। एक मार्च से ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रहे विमंस एशियन कप में नॉर्थ कोरिया की महिला फुटबॉल टीम हिस्सा लेने जा रही है। लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लगभग गायब रहने के 16 साल बाद वर्ल्ड नंबर-9 टीम टूर्नामेंट में उतर रही है। नॉर्थ कोरिया के महिला फुटबॉल की कहानी 1986 में शुरू हुई थी। कहा जाता है कि जब फीफा कांग्रेस में महिलाओं के लिए वर्ल्ड कप की मांग उठी, तो नॉर्थ कोरियाई प्रतिनिधियों ने इसे अपनी गिरती राजनीतिक साख को बचाने के एक मौके के तौर पर देखा। नॉर्थ कोरिया ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत महिलाओं के खेल में भारी निवेश किया। स्कूल पाठ्यक्रम में फुटबॉल कार्यक्रम जोड़े गए, सेना में महिला टीमें बनाई गईं और देशभर में फुटबॉल से जुड़ी फेसिलिटी तैयार की गईं। तत्कालीन नेता किम जोंग-इल (फुटबॉल प्रेमी) ने महिला फुटबॉल को 'पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा' का जरिया बनाया। 2010 तक नॉर्थ कोरिया एशिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक थी। 2011 में टीम की रफ्तार पर तब ब्रेक लग गया, जब वर्ल्ड कप के दौरान पांच खिलाड़ी डोप टेस्ट में फेल हो गईं। तब नॉर्थ कोरिया ने अजीबो-गरीब दलील दी थी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों पर बिजली गिरी थी, जिसके इलाज के लिए उन्हें 'कस्तूरी मृग' की ग्रंथियों से बनी प्राकृतिक दवा दी गई थी।

फास्ट न्यूज

अरिजीत सिंह की आमिर के साथ काम करने पर सफाई

मुबंई। अरिजीत सिंह ने जनवरी में प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने आमिर खान के प्रोडक्शन की फिल्म एक दिन के लिए गाना गाया। ऐसे में एक्टर के बदलते फैसले पर सवाल उठाए गए और उनकी आलोचना की गई। ऐसे में सिंगर ने अब खुद इस पर सफाई दी है। अरिजीत सिंह ने मंगलवार को आधिकारिक X अकाउंट (पहले ट्विटर) पर लिखा है।

मां बनने के बाद कटरीना की पहली पब्लिक अपीयरेंस

नई दिल्ली। कटरीना कैफ मां बनने के बाद पहली बार पब्लिकली नजर आई हैं। एक्ट्रेस ने 7 नवंबर 2025 को बेटे को जन्म दिया था, इसके बाद से ही वो कहीं भी स्पॉट नहीं हुई हैं। लंबे समय बाद एक्ट्रेस पब्लिकली आईं, हालांकि इस दौरान उन्होंने मास्क से अपना चेहरा छिपा रखा था। मंगलवार को कटरीना कैफ को सेलिब्रिटी पिलाटे ट्रेनर यासमिन कराचीवाला के साथ स्पॉट किया गया है। इस दौरान उन्होंने व्हाइट टी-शर्ट के साथ ब्लैक जैकेट पहन रखी थी। बंधें बालों में एक्ट्रेस ने ब्लैक मास्क से चेहरा छिपाया हुआ था। सामने आए वीडियो में एक्ट्रेस का वजन काफी बढ़ा हुआ लग रहा है। स्पॉटिंग के दौरान एक्ट्रेस ने मेकअप नहीं किया था। अचानक हुई स्पॉटिंग के बाद एक्ट्रेस कैमरों से बचती नजर आईं, हालांकि बाद में उन्होंने पैपराजी को वेव किया।

अमेरिका के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के टॉयलेट जाम

तेल अवीव। ईरान की तरफ बढ़ रहा अमेरिकी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड एक अलग ही संकट से जूझ रहा है। जहाज के ज्यादातर टॉयलेट जाम हो चुके हैं। इससे 4,500 से ज्यादा नौसैनिकों को रोज 45 मिनट तक लाइन में लगना पड़ रहा है। संकरी पाइप-लाइन और वैक्यूम-बेस्ड सिस्टम की डिजाइन में खामी के चलते टॉयलेट बार-बार जाम हो रहे हैं।

'कांतारा' विवाद को लेकर रणवीर सिंह को फटकार

हाईकोर्ट ने कहा-सेलिब्रिटी होने से धार्मिक भावनाएं आहत करने का अधिकार नहीं

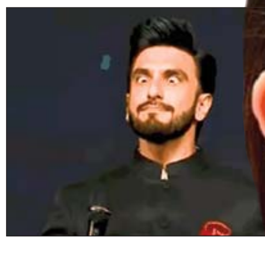

मुबंई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक्टर रणवीर सिंह को 'कांतारा' विवाद मामले में फटकार लगाते हुए कहा कि आपको अपने बयानों में जिम्मेदार होना चाहिए। सिर्फ सेलिब्रिटी होने के कारण उन्हें किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने एक्टर से यह भी कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाते समय उन्हें अपने शब्दों और व्यवहार में सावधानी बरतनी चाहिए। ढीली-ढाली भाषा बिल्कुल नहीं चल सकती। आप रणवीर सिंह हों या कोई। वहीं, कोर्ट ने रणवीर को अंतरिम राहत भी दी और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए। मामले की अगली सुनवाई सोमवार, 2 मार्च को होगी। रणवीर सिंह की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट साजन पूवैय्या ने कोर्ट में शुरुआत में ही एक्टर की टिप्पणी को पूरी तरह असंवेदनशील बताते हुए दुख जताया। उन्होंने कहा कि रणवीर का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना नहीं था। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, "आप एक एक्टर हैं, कई लोग आपसे प्रभावित होते हैं। इसलिए जिम्मेदारी जरूरी है। मिमिक्री करना अलग बात है, लेकिन किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने का अधिकार नहीं। माफी से क्या शब्द वापस आ जाएंगे? हम भूल सकते हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं भूलता।"

प्रोसीजर के बाद भी बना हुआ है दर्द, पति शोएब इब्राहिम बोले- चिंता की कोई बात नहीं है

दीपिका कक्कड़ के 13 एमएम सिस्ट की सर्जरी हुई

मुबंई। बीते साल लिवर कैंसर को मात दे चुकीं एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के पेट में हाल ही में 13एमएम का एक सिस्ट डिटेक्ट हुआ था। इस डायग्नोज से एक्ट्रेस बेहद डर गईं क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि कैंसर फिर हो सकता है। अब 24 फरवरी को एक्ट्रेस की सिस्ट में लेजर प्रोसीजर किया गया है। उनके पति और एक्टर शोएब इब्राहिम ने दीपिका की हेल्थ का अपडेट देते हुए बताया है कि वो प्रोसीजर अच्छी तरह हुआ, जिसके बाद अब एक्ट्रेस ठीक हैं। हालांकि उन्हें कुछ समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा। कुछ समय पहले ही शोएब और दीपिका ने व्लॉग के जरिए बताया था कि 20 फरवरी को एक्ट्रेस के पेट में तेज दर्द हुआ। अगले दिन दर्द काफी बढ़ गया, जिसके बाद वो हॉस्पिटल गए। सीटी स्कैन करवाने पर सामने आया कि एक्ट्रेस के पेट में 13 एमएम का सिस्ट है। क्योंकि एक्ट्रेस को पेट और कंधे में दर्द था, तो वो काफी डरी हुई थीं, क्योंकि बीते साल भी यही लक्षण होने के बाद उन्हें लिवर कैंसर डायग्नोज हुआ था।

लेजर प्रोसीजर के बाद शोएब इब्राहिन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो लिखते हैं, अल्लाह के करम से और आप सभी की दुआओं से डिप्पी (दीपिका) का प्रोसीजर पूरा हो गया है। सब कुछ अच्छी तरह से हुआ। वह भी ठीक है, बस थोड़ा दर्द में है।

बीते साल हुआ था स्टेज-2 लिवर कैंसर

एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ बीते साल सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का हिस्सा थीं। हालांकि तबीयत बिगड़ने के बाद उन्होंने शो छोड़ दिया था। उन्हें कंधे में तेज दर्द बना हुआ था। जांच करवाने में सामने आया कि उनके लिवर में एक टेनिस बॉल जितना बड़ा सिस्ट है। जांच में ये भी सामने आया कि ये एक तरह का कैंसर है।

जून 2025 में एक्ट्रेस का 14 घंटे का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें उनके लिवर और गालब्लेडर का 22 प्रतिशत हिस्सा काटकर अलग कर दिया गया। एक्ट्रेस कैंसर फ्री हो गई थीं। हालांकि अब उन्हें डर है कि कहीं दोबारा उन्हें इसका सामना न करना पड़े।

5 लाख घरों की बिजली गुल, 153 साल में पहली बार अखबार नहीं छप सका

बर्फीले तूफान से 11 हजार फ्लाइट रद्द

वॉशिंगटन, एजेंसी

अमेरिका में भीषण तेज हवाओं और भारी बर्फबारी के कारण एयरपोर्ट पर रनवे बंद करने पड़े और कई जगह उड़ानों पर रोक लगानी पड़ी है। यहां रविवार से मंगलवार के बीच 11,055 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं। सिर्फ सोमवार को ही करीब 5,600 से 5,700 उड़ानें कैंसिल हुईं, जो देशभर की उड़ानों का लगभग 20% था। यह जानकारी फ्लाइट ट्रैकिंग कंपनी फ्लाइटअवेयर ने दी। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक, रोड आइलैंड और मैसाचुसेट्स के कुछ हिस्सों में लगभग 37 इंच तक बर्फ गिरी। बर्फबारी की वजह से उत्तर-पूर्वी राज्यों में 6 लाख से ज्यादा घरों की बिजली चली गई। सोमवार शाम तक 5 लाख 19 हजार 232 घर और ऑफिस बिना बिजली के थे। भारी बर्फबारी के कारण द बोस्टन ग्लोब अपने 153 साल के इतिहास में पहली बार अखबार नहीं छाप सका क्योंकि कर्मचारी प्रिंटिंग प्रेस तक नहीं पहुंच पाए। वहीं मैसाचुसेट्स की गवर्नर मॉरा हीली ने कुछ इलाकों में ट्रैवल बैन लागू किया और लोगों से घर में रहने की अपील की। रोड आइलैंड के गवर्नर डैन मैकी ने भी पूरे राज्य में ट्रैवल बैन लगा दिया। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने भी पूरे राज्य में इमरजेंसी की घोषणा की और नेशनल गार्ड को अलर्ट पर रखा है। तूफान का असर सिर्फ सड़कों और हवाई सेवाओं तक सीमित नहीं रहा। न्यूयॉर्क और बोस्टन के बीच ट्रेन सेवा सोमवार रात तक सस्पेंड रही। थिएटर ब्रॉडवे के सभी शो रविवार शाम रद्द कर दिए गए। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा कि यह पिछले लगभग एक दशक का सबसे शक्तिशाली नॉरईस्टर तूफान है। कई इलाकों में प्रति घंटे 2 से 3 इंच तक बर्फ गिरने की चेतावनी दी गई है और हवा की रफ्तार कुछ जगह 110 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई। नॉरईस्टर एक तरह का तेज तूफान होता है जो अमेरिका के पूर्वी तट पर आता है। इसे नॉरईस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हवाएं आमतौर पर उत्तर-पूर्व (नॉर्थ-ईस्ट) दिशा से चलती हैं।

■ अमेरिका में भीषण बर्फबारी जारी है। सड़कें पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं।

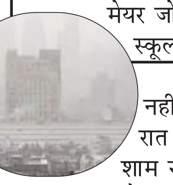

बर्फबारी से कई राज्यों में इमरजेंसी घोषित

न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में रविवार से सोमवार के बीच करीब 20 इंच बर्फ दर्ज की गई, जबकि लॉन्ग आइलैंड के इस्लिप इलाके में 22 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ी। प्रोविडेंस, रोड आइलैंड में 32.8 इंच बर्फबारी हुई, जिसने 1978 के पुराने रिकॉर्ड 28.6 इंच को तोड़ दिया। हालात इतने खराब हो गए कि कई राज्यों में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। न्यूयॉर्क सिटी में स्कूलों, सड़कों, पुलों और हाईवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। बाद में हालात सुधरने पर मेयर जोहरान ममदानी ने यह आदेश हटा लिया और कहा कि स्कूल मंगलवार को खुलेंगे।

गर्म और नम हवा मिलकर बनाती है यह तूफान

अमेरिका के उत्तर-पूर्व में आने वाला यह विंटर स्टॉर्म इसलिए बनता है क्योंकि वहां मौसम की कुछ खास स्थितियां एकसाथ बन जाती हैं। सर्दियों में कनाडा की तरफ से बहुत ठंडी हवा नीचे की ओर आती है। उसी समय समुद्र की तरफ से हल्की गर्म और नम हवा ऊपर उठती है। जब ये दोनों आमने-सामने आती हैं तो मौसम अचानक बिगड़ जाता है और तेज बर्फीला तूफान बन जाता है।

भारत-पाकिस्तान जंग रुकवाई : ट्रम्प

गाजा सीजफायर बड़ी जीत, वेनेजुएला नया दोस्त

वॉशिंगटन, एजेंसी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह संसद में भाषण दिया। साल की शुरुआत में संसद में प्रेसिडेंट के भाषण को 'स्टेट ऑफ द यूनियन' स्पीच कहा जाता है। ट्रम्प ने 1 घंटा 50 मिनट के भाषण में एक बार फिर भारत-पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया। ट्रम्प यह बात 100 से ज्यादा बार दोहरा चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हवाले से कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु जंग में 3.5 करोड़ लोगों के मारे जाने की आशंका थी। हालांकि, भारत इस दावे को हमेशा खारिज करता आया है। अपने भाषण में ट्रम्प ने इजराइल-हमास के बीच गाजा सीजफायर को अपनी उपलब्धि कहा। वहीं वेनेजुएला पर कब्जे के करीब डेढ़ महीने बाद वहां तेल उत्पादन में बढ़ोतरी का दावा करते हुए उसे अमेरिका का नया दोस्त करार दिया। ट्रम्प ने ईरान को लेकर दावा किया कि अमेरिका ने पिछले साल जुलाई में हमला कर उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया था। साथ ही 28 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 32 हजार प्रदर्शनकारियों को मारने का आरोप भी लगाया।

तेजी : 10 ग्राम ₹1.60 लाख पर पहुंचा, चांदी ₹6,455 बढ़कर ₹2.69 लाख किलो हुई

सोना 3 दिन में ₹5 हजार महंगा हुआ

नई दिल्ली, एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय बाजार और घरेलू मांग के असर से सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बुधवार, 25 फरवरी को सोना और चांदी दोनों की कीमतों में मजबूत उछाल दर्ज किया गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत में 582 रुपए प्रति 10 ग्राम की वृद्धि हुई है, जिसके बाद इसका भाव बढ़कर 1,59,823 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 1,59,241 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। यह लगातार तीसरा कारोबारी दिन है जब सोने की कीमत में तेजी दर्ज की गई है। पिछले तीन दिनों में ही सोना करीब 5,000 रुपए तक महंगा हो चुका है, जिससे निवेशकों और खरीदारों के बीच हलचल तेज हो गई है। सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी बड़ी तेजी दर्ज की गई है। IBJA के मुताबिक, चांदी की कीमत में आज 6,455 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद चांदी का भाव बढ़कर 2,69,367 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। इससे पहले चांदी की कीमत 2,62,912 रुपए प्रति किलो थी। चांदी की कीमतों में यह बढ़ोतरी औद्योगिक मांग और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी का संकेत मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में चांदी में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

इस साल सोना 27,000 रुपए और चांदी 39,000 रुपए महंगी हुई

इस साल सोने-चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 27,000 रुपए और चांदी 39,000 रुपए महंगी हो चुकी है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपए और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का ऑल टाइम हाई भी बनाया था।

1.80 लाख तक जा सकता है सोना

इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी UBS के अनुसार सोने की मांग में तेजी बनी हुई है। 2025 में दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों ने 863 टन सोना खरीदा था। अब अनुमान है कि 2026 में यह खरीदारी बढ़कर 950 टन तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही, गोल्ड ईटीएफ (ETF) में निवेश भी बढ़कर 825 टन होने की उम्मीद है। UBS को पूरा भरोसा है कि 2026 में सोने की कीमतें और ऊपर जाएंगी। रिपोर्ट के अनुसार, साल के बीच तक सोना 6,200 डॉलर प्रति औंस के ऊंचे स्तर को छू सकता है।

सोने-चांदी के दाम में तेजी के 3 प्रमुख कारण

- दुनिया के केंद्रीय बैंक लगातार बहुत ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। वे डॉलर पर कम निर्भर होना चाहते हैं, इसलिए सोने को रिजर्व में डाल रहे हैं।
- अमेरिकी फेड से इस साल ब्याज दरें घटाने के संकेत दिए हैं। दरें कम होने पर गोल्ड जैसी चीजों की डिमांड बढ़ जाती है।
- जियो पॉलिटिकल टेंशन (मिडिल ईस्ट, ईरान-अमेरिका, अन्य वैश्विक विवाद) बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में लोग सुरक्षित निवेश के लिए सोने-चांदी को अपना रहे हैं।

700 अंक चढ़ने के बाद फ्लैट हुआ सेंसेक्स

मुंबई। सेंसेक्स आज यानी बुधवार 25 फरवरी को 700 अंक चढ़ने के बाद फ्लैट हो गया है। ये अब मामूली बढ़त के साथ 82,2000 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में करीब 30 अंक की तेजी है। ये 25,450 के स्तर पर आ गया है। आज के कारोबार में मेटल-आईटी शेयरों में खरीदारी है। सरकार रेलवे की फाइनेंस कंपनी IRFC में अपनी 4% तक हिस्सेदारी बेच रही है। यह बिक्री ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए की जा रही है। यह ऑफर नॉन-रिटेल निवेशकों के लिए आज से खुल गया है। वहीं, रिटेल निवेशक गुरुवार, 26 फरवरी को अपनी बोलियां लगा सकेंगे। इसके लिए फ्लोर प्राइस 104 प्रति शेयर तय किया गया है। मंगलवार, 24 फरवरी को IRFC का शेयर 109.40 पर बंद हुआ था। यानी सरकार निवेशकों को मौजूदा कीमत से डिस्काउंट पर शेयर ऑफर किया है। हालांकि आज ये शेयर करीब 4% नीचे 105 रुपए पर आ गया है। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस के IPO का आज आखिरी दिन है। ये 24 फरवरी तक 0.47 गुना सब्सक्राइब हुआ है।

भारतीय सोलर पैनल पर अमेरिका ने 126% ड्यूटी लगाई

कहा- चीन भारत के जरिए भेज रहा सस्ते प्रोडक्ट, लाओस और इंडोनेशिया पर भी टैक्स

वॉशिंगटन, एजेंसी

अमेरिका ने भारत से आने वाले सोलर पैनलों और सेल पर 126% की शुरुआती ड्यूटी लगा दी है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग का कहना है कि भारत अपने मैन्युफैक्चरर्स को गलत तरीके से सब्सिडी दे रहा है, जिससे अमेरिकी घरेलू कंपनियों को नुकसान हो रहा है। भारत के अलावा लाओस और इंडोनेशिया पर भी 81% से 143% तक की लेवी लगाई गई है। शुरुआती जांच के आधार पर यह फैसला लिया गया है। जांच पर अंतिम फैसला 6 जुलाई को आएगा। यानी सब्सिडी की बात साबित हो जाती है, तो यह टैक्स स्थायी हो जाएगा। इस फैसले से भारतीय सोलर एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिकी बाजार में टिकना मुश्किल हो सकता है। 126% ड्यूटी लगने का मतलब है कि इन पैनलों की कीमत अमेरिका में दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में अमेरिकी खरीदार भारतीय माल के बजाय लोकल कंपनियों या अन्य देशों से पैनल खरीदना पसंद करेंगे क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट अब कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे। यह टैक्स उन 10% ग्लोबल टैरिफ से अलग है, जिसकी घोषणा ट्रम्प ने हाल ही में की थी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ट्रम्प के पुराने टैरिफ प्लान को रद्द कर दिया था जिसके बाद उन्होंने नए सिरे से टैरिफ लगाए थे। अब इस नए फैसले ने इंडस्ट्री की चिंता बढ़ा दी है। ब्लूमबर्ग एनईएफ के के मुताबिक, 2025 की पहली छमाही में अमेरिका में होने वाले कुल सोलर मॉड्यूल आयात का 57% हिस्सा भारत, इंडोनेशिया और लाओस से आया था। भारतीय एक्सपोर्ट की बात करें तो 2024 में अमेरिका को 792.6 मिलियन डॉलर (करीब 7,200 करोड़ रुपए) के सोलर उत्पाद भेजे गए थे, जो 2022 की तुलना में 9 गुना ज्यादा है। चीनी प्रोडक्ट को भारत-इंडोनेशिया के जरिए भेजने का आरोप अमेरिकी सोलर मैन्युफैक्चरर्स का आरोप है कि चीनी कंपनियां अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए भारत, इंडोनेशिया और लाओस जैसे देशों के रास्ते अपना माल भेज रही हैं। पहले चीन ने वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब वहां सख्ती हुई तो उन्होंने भारत और अन्य एशियाई देशों में प्रोडक्शन शिफ्ट कर दिया।

200 मंडल अध्यक्षों का ऐलान, यूपी बीजेपी अध्यक्ष बोले- डेढ़ दो सौ क्यों खर्च किए, तुम्हारे काम आता

पंकज चौधरी को बायोडेटा सौंपने की होड़

अभिनंदन

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव आने वाला है और सभी को काम मिलेगा, हर किसी के लिए काम है। बुधवार को लखनऊ में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे। एक कार्यकर्ता ने उन्हें भगवा गमछा पहनाकर अभिनंदन किया। इस पर उन्होंने कहा, "इसमें पैसा क्यों खर्च किया? डेढ़-दो सौ रुपए जो खर्च किए, वह तुम्हारे काम आते।" वहीं, एक अन्य कार्यकर्ता ने उन्हें बुलडोजर की रेप्लिका भेंट की। बुलडोजर देखकर पंकज चौधरी मुस्कुरा उठे और बोले, "पूरा बुलडोजर ही उठा लाए हो।" बड़ी संख्या में महिलाएं भी मिलने पहुंची थीं। दरअसल, भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की कवायद शुरू

हो चुकी है। शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अपनी नई टीम बनाने में जुट गए हैं। नई टीम में जगह पाने के लिए प्रदेशभर से नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अपना दावा मजबूत करने के लिए अधिकतर कार्यकर्ता बायोडेटा भी सौंप रहे हैं। उधर, मंगलवार देर रात को भाजपा ने 200 मंडल अध्यक्षों और जिला प्रतिनिधियों के नामों की सूची जारी की है। बुधवार को 14 जिलाध्यक्षों की लिस्ट भी सामने आ सकती है। भाजपा बुधवार शाम तक 14 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर सकती है।

महिला कार्यकर्ता भी पद मांगने पहुंची

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मिलने बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी पहुंची। इन लोगों ने उनसे मुलाकात कर नई कार्यकारिणी के लिए अपना दावा किया। कई महिला कार्यकर्ताओं ने अपना बायोडेटा भी उनको सौंपा। नए प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंचे कार्यकर्ता उनका अभिनंदन करने के बाद जिला से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी में जगह पाने के लिए अपना दावा करते हुए बायोडेटा भी सौंप रहे।

2 मार्च को होली मिलन करेंगे चौधरी

पंकज चौधरी 2 मार्च को प्रदेश कार्यालय में होली मिलन करेंगे। चौधरी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलकर होली की शुभकामनाएं देंगे। दरअसल, भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल होली के बाद होना है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम को लेकर पहले दौर का मंथन पूरा हो चुका है। लेकिन, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर पेंच फंसा है। ऐसे में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दूसरे दौर की बैठकों के बाद ही अंतिम मुहर लगेगी।

जो भी पहुंचा उससे मिले नए प्रदेश अध्यक्ष

प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए सुबह 10 से 12 बजे तक का समय निर्धारित किया था। लेकिन दूर-दराज के जिलों से कार्यकर्ता काफी देर तक कार्यालय पहुंचते रहे। पंकज चौधरी ने निर्धारित समय-सीमा के बाद भी आए सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी एक-एक बात सुनी। प्रदेश सरकार के मंत्री जसवंत सैनी ने मिलकर शादी का कार्ड दिया। भाजपा ने 1918 संगठनात्मक मंडलों में से शेष रहे करीब दो सौ मंडलों में भी जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने मंगलवार को मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की।

- बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी उनसे मिलीं और अपना बायोडेटा जमाकर नई कार्यकारिणी के लिए दावा किया।
- प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंचा एक कार्यकर्ता अपने कार्यों की क्लिपिंग वाली बुकलेट लेकर पहुंचा।
- गमछा पहनाकर अभिनंदन करने के बाद कार्यकर्ता अपना बायोडेटा भी दिया।

पंकज चौधरी ने पद और काम मांगने वाले कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी का काम करते रहो, संगठन से जो काम दिए जा रहे हैं उन्हें नीचे तक पहुंचाओ। पार्टी में आगे काम के आधार पर ही आपके बारे में निर्णय किया जाएगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा- चुनाव आने वाले हैं। सबके लिए काम है।

अखिलेश यादव का भाजपा पर आरोप

बोले- मतदाताओं को नोटिस भेजना 'वोटबंदी अभियान'

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मतदाताओं को बड़े पैमाने पर नोटिस भेजे जाने को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे नोटबंदी के बाद भाजपा का नया "वोटबंदी अभियान" बताया और कहा कि सरकार की नीयत पहले भी खराब थी और अब भी खराब बनी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले केवल मुसलमानों को कागजों के नाम पर परेशान किया जाता था, लेकिन अब हिंदू समुदाय के लोगों को भी लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब वोट के आधार पर नागरिकता तय की जाएगी और लोगों को उनके खेत, जमीन और मकानों से बेदखल किया जाएगा? उन्होंने कहा कि कुछ लोग दावा कर रहे थे कि गलत वोट पाए जाने पर संबंधित लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सपा प्रमुख ने कहा कि जब महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के परिजनों तक को नकार दिया गया, तो आम लोगों की स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि लोगों के पास वोटर कार्ड या संबंधित दस्तावेज नहीं होंगे।

फास्ट न्यूज

रामादेवी से गोल चौराहे तक बनेगा 4-लेन एलीवेटेड कॉरिडोर

कानपुर। कानपुर में रामादेवी से गोल चौराहे तक 10.160 किलोमीटर लंबे मार्ग पर फोर लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद इस व्यस्त मार्ग पर यातायात का दबाव कम होगा। आम लोगों को जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि अभी क्रॉसिंग बंद होने पर लंबा जाम लगता है, 10 मिनट की दूरी तय करने में घंटेभर लग जाते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इस परियोजना को मंजूरी मिलने की जानकारी दी।

10 साल के मासूम को उठाकर अपने बराबर से पटका

लखनऊ। लखनऊ के गोलागंज इलाके में एक 10 वर्षीय रोजेदार बच्चे को एक युवक ने उठाकर पक्की नाली में पटक दिया। बच्चा बेहोश हो गया। वह नमाज पढ़ने के बाद घर पास अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बच्चे का उपचार चल रहा है। गोलागंज निवासी 10 वर्षीय अब्दुल नासिर पुत्र हयात हुसैन 20 फरवरी को रोजा खोलने के बाद मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। नमाज के बाद वह मस्जिद के बाहर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगा। आरोप है कि तभी मोहल्ले में रहने वाला 22 वर्षीय फहद उर्फ प्रिंस वहां पहुंचा। उसने नासिर को गर्दन और दोनों पैरों के बीच से पकड़कर सिर से ऊपर उठा लिया। पूरी ताकत से पक्की गली में पटक दिया। बच्चा बेहोश हो गया। घटना के बाद आरोपी के चाचा राशिद और घर की महिलाएं बच्चे को उसके घर ले गईं।

फर्जी मार्कशीट गिरोह के सरगना के मिले 5 अकाउंट

कानपुर। फर्जी डिग्री और मार्कशीट मामले में पूरे नेटवर्क की जड़ें खंगालने के लिए जुटी SIT की टीमें मंगलवार को अलीगढ़, हापुड़, मेरठ, शिकोहाबाद जांच और छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय पहुंची। टीम ने यहां कई घंटों तक जांच-पड़ताल की। इस दौरान पुलिस ने बरामद 900 मार्कशीट, डिग्री और माइग्रेशन सर्टिफिकेट असली हैं या नकली इसकी जांच की। इन सब के अलावा SIT को शैलेंद्र के 5 अकाउंट भी मिले हैं।

रोडवेज संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन

13 सूत्री मांगों को लेकर मार्च किया, स्वास्थ्य भवन से कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली

- रोडवेज कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य भवन के पास से कलेक्ट्रेट तक मार्च किया।
- कर्मचारियों ने आज का दिन विरोध दिवस के रूप में मनाया।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) के संविदा कर्मचारियों ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने स्वास्थ्य भवन चौराहे से जिलाधिकारी कार्यालय लखनऊ तक पैदल मार्च निकालते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और संविदा व्यवस्था समाप्त कर नियमितीकरण की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी सड़कों पर उतरे और सरकार तथा परिवहन निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि वे वर्षों से निगम में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर लगातार

अनदेखी की जा रही है। स्वास्थ्य भवन चौराहे से जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाले गए इस मार्च के कारण कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही। हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित कर यातायात को सामान्य कराया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को न तो स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं मिल रही हैं और न ही वेतनमान में समानता है। उन्होंने मांग की कि संविदा व्यवस्था को समाप्त कर उन्हें नियमित किया जाए, ताकि उन्हें सेवा सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। कर्मचारियों ने बताया कि वे लंबे समय से निगम के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें स्थायी कर्मचारियों के बराबर अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। कर्मचारियों द्वारा प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में कुल 13 मांगें शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, वेतन वृद्धि, बकाया भुगतान, सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करना, ड्यूटी घंटों में सुधार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ने पर प्रदेशभर में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

13 सूत्री मांगों पर ठोस निर्णय की मांग

कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है, लेकिन यदि जल्द ही मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि वे सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।

प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

डीएम कार्यालय के अधिकारियों ने कर्मचारियों का ज्ञापन प्राप्त कर शासन स्तर पर भेजने का आश्वासन दिया। फिलहाल, कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं की जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि जनपद बस्ती के बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में स्थाई रूप से स्थानांतरित (Permanently Deleted) मतदाताओं के नाम भाजपा पदाधिकारियों के दबाव में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से रोल बैक कराकर फिर से मतदाता सूची में दर्ज करा दिए गए। पार्टी का आरोप है कि इस प्रक्रिया में ईआरओ (Electoral Registration Officer) और बीएलओ की भूमिका संदिग्ध रही है, जिससे मतदाता सूची की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

ज्ञापन के अनुसार, बस्ती सदर विधानसभा के पोलिंग बूथ संख्या-190 पर मतदाता क्रम संख्या 102, 104, 105, 468, 475, 477, 469 और 479 के नाम पहले स्थाई रूप से स्थानांतरित सूची में दर्ज थे, लेकिन बाद में इन्हें दोबारा मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा इन मतदाताओं के नाम अन्य पोलिंग बूथों जैसे बूथ संख्या-102, 363 और 387 पर भी दर्ज पाए गए, जिससे एक ही मतदाता का नाम दो-दो जगह दर्ज होने का मामला सामने आया है। पार्टी ने इसे डुप्लीकेट मतदाता की श्रेणी में आने वाला गंभीर मामला बताया है। ज्ञापन में कहा गया है कि पोलिंग बूथ संख्या-120, 151, 208, 183, 403, 404, 399, 216, 381, 387, 218, 325, 168, 195, 187, 55, 177, 60, 130 और 436 सहित कई बूथों पर भी स्थाई रूप से हटाए गए मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ दिए गए हैं। पार्टी का दावा है कि इस तरह कई मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हो गए हैं, जिससे मतदाता सूची की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए तथा यदि किसी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की अनियमितता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर असर डाल सकती है, इसलिए इस मामले को गंभीरता से लिया जाना आवश्यक है।

करोड़ों की बिल्डिंग में 'घटिया खेल'!

राजकीय इंटर कॉलेज में निर्माण पर प्रधानाचार्य के तीखे आरोप

तमसा संकेत, संवाददाता

बहराइच। जिले में शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। सरकारी नई किताबों के कबाड़ी तक पहुंचने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब जिले के प्रतिष्ठित राजकीय इंटर कॉलेज बहराइच में बन रहे नए भवन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। दरगाह शरीफ क्षेत्र स्थित इस ऐतिहासिक विद्यालय की जर्जर इमारत को गिराकर सरकार ने करोड़ों रुपये की लागत से नए भवन के निर्माण को मंजूरी दी थी, ताकि छात्रों को सुरक्षित और आधुनिक शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य नागेंद्र कुमार ने निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी और घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है, जिससे पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। प्रधानाचार्य नागेंद्र कुमार ने आरोप लगाया है कि नए भवन के निर्माण में निम्न गुणवत्ता की ईंट और

अन्य निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। उनका कहना है कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा और इस संबंध में कई बार संबंधित एजेंसी को शिकायत भी की गई है, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि इसी तरह लापरवाही जारी रही, तो भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानाचार्य के इस बयान के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आ गई हैं। प्रधानाचार्य ने निर्माण कार्य की जिम्मेदारी संभाल रही उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं अवसंरचना विकास निगम (UPSID-CO) पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद एजेंसी द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और निर्माण कार्य उसी तरीके से जारी है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि जब विद्यालय प्रशासन खुद निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहा है।

वारदात : झांसी से बर्थ-डे पार्टी में एमपी ले गई, लवर से बोली-लौटना नहीं चाहिए, फिर गला घोंटा

पत्नी ने प्रेमी देवर से पति की हत्या कराई

तमसा संकेत, एजेंसी

झांसी। झांसी के एक युवक की मध्य प्रदेश में हत्या कर दी गई। इस हत्या को उसकी पत्नी, उसके प्रेमी और एक साथी ने मिलकर अंजाम दिया। महिला और उसके प्रेमी देवर के बीच अवैध संबंध थे, जिसमें पति रोड़ा बन रहा था। दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 4 फरवरी को युवक अपने बुआ के घर बर्थ-डे पार्टी में ग्वालियर गया था। इसी दौरान पत्नी ने प्रेमी को से कहा- आज लौटना नहीं चाहिए। इसके बाद प्रेमी ने युवक को शराब पिलाई और बाइक से दतिया के गोराघाट ले गया। वहां मफलर से गला घोंटकर युवक की हत्या कर दी गई और शव को सिंध नदी के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया। 6 फरवरी को पुलिस को शव मिला। पोस्टमॉर्टम में गला घोटने से मौत की पुष्टि हुई। लेकिन शिनाख्त नहीं होने के कारण पुलिस ने शव को दफना दिया। 9 फरवरी को परिजन हंसराज की

हेमंत – आरोपी भाई | अनिल खटीक – आरोपी | बबिता – आरोपी पत्नी

तलाश में गोराघाट थाने पहुंचे। फोटो दिखाने पर शव की शिनाख्त हो गई। अब पुलिस ने महिला, उसके प्रेमी और उसके साथी खटीक को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना युवक की पहचान हंसराज वर्मा (37) के रूप में हुई। वह सदर थाना क्षेत्र के भगवंतपुरा गांव का निवासी था। हंसराज की शादी 16 साल पहले बबीता से हुई थी और उनके दो बच्चे हैं। वह पुराना तेल खरीद-फरोख्त का काम करता था। हंसराज के ताऊ ग्वालियर में रहते हैं। एक साल पहले होली के मौके पर हंसराज के परिवार में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान ताऊ के बेटे हेमंत भी पहुंचे और उनकी मुलाकात बबीता से हो गई। कुछ ही दिनों में यह मुलाकात प्यार में बदल गई। हेमंत ग्वालियर में पॉली बैग (पॉलीथिन) की फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम करता है। इसके बाद हेमंत ने बबीता की आर्थिक मदद करना शुरू किया।

बबीता ने पुलिस को बताया कि पति हंसराज शराब पीता था और उसे हमारे प्रेम संबंधों के बारे में शक था। इसी वजह से वह आए दिन मुझसे मारपीट करता था। इस कारण मैंने प्रेमी हेमंत के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। 4 फरवरी को हंसराज अपनी बुआ के घर ग्वालियर में जन्मदिन की पार्टी में गया था। तब उसने हेमंत को अपनी लोकेशन बताई और कहा कि आज लौटना नहीं चाहिए।

पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि, पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया

6 फरवरी को गोराघाट थाना क्षेत्र में हाईवे पर सिंध नदी पुल के नीचे झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। इस कारण पुलिस ने शव को दफना दिया।

पृष्ठ 01 का शेष...

'ज्यूडीशियल ...

यह निंदनीय है। सिंघवी ने कहा कि NCERT ने मान लिया है कि राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और अन्य संस्थानों में भ्रष्टाचार है ही नहीं। NCERT चेयरमैन दिनेश प्रसाद सकलानी का इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं आया है। काउंसिल के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए वे इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। इस बीच सरकारी सूत्रों ने कहा कि भले ही NCERT एक ऑटोनॉमस संस्था है, लेकिन चैप्टर जोड़ने से पहले अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए था। सरकारी सूत्रों ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा शामिल करना था, तो उसमें शासन के तीनों अंगों- कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को भी जोड़ा जाना चाहिए था। सरकारी सूत्रों ने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित आंकड़े संसदीय अभिलेखों और नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड में मौजूद हैं, लेकिन फैक्ट्स के क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए केंद्र से परामर्श नहीं लिया गया। इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार, बड़ी संख्या में पेंडिंग मामले और जजों की भारी कमी ज्यूडिशियल सिस्टम के सामने प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं। जज आचार संहिता से बंधे होते हैं, जो न केवल कोर्ट में उनके व्यवहार को कंट्रोल करता है, बल्कि कोर्च के बाहर उनके आचरण को भी तय करती है। किताब के एक सेक्शन का टाइटल 'Justice delayed is justice denied' है। इसका मतलब है- इंसाफ में देरी इंसाफ न मिलने जैसा है। यहां सुप्रीम कोर्ट में 81 हजार, हाईकोर्ट्स में 62 लाख 40 हजार, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के 4 करोड़ 70 लाख पेंडिंग केस की संख्या भी बताई गई है।

ओडिशा माइनिंग ...

इसके अलावा अफसर के नाम करीब 130 ग्राम सोना और 2400 वर्गफीट का प्लॉट है, जिस पर दो मंजिला बिल्डिंग बन रही है। मोहंती के नाम 10 बैंक खाते और लॉकर भी हैं, जिनकी जांच की जा रही है। विजिलेंस अधिकारियों ने इसे ओडिशा विजिलेंस के इतिहास की सबसे बड़ी नगद बरामदगी बताया है। इससे पहले विजिलेंस की सबसे बड़ी नगद जब्ती 3.4 करोड़ थी, जो 7 अप्रैल 2022 को गंजाम जिले में लघु सिंचाई विभाग के एक असिस्टेंट इंजीनियर के घर से मिली थी। एसपी समल ने बताया कि मोहंती के खिलाफ 2009 में भी भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ था। उस मामले की सुनवाई मयूरभंज जिला कोर्ट में अभी चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि मोहंती ने 2004 में 8 हजार वेतन पर जूनियर माइनिंग ऑफिसर के तौर पर सरकारी सेवा शुरू की थी। वे बोलांगीर, बारीपदा और बरहामपुर में काम कर चुके हैं और फिलहाल कटक में तैनात थे। इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बरामदगी राज्य में चल रहे "डबल इंजन सरकार" के दौरान पनप रहे बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करती है।

यूपी में जितनी ...

योगी ने अयोध्या में दीपोत्सव का जिक्र किया और कहा कि साल 2017 से पहले दीपावली इस भव्यता के साथ नहीं मनाई जाती थी। सरकार बनने के बाद दीपोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया गया। पहली बार जब दीप प्रज्ज्वलन की योजना बनी, तब 51 हजार दीपक भी अयोध्या और आसपास उपलब्ध नहीं थे। उस समय पूरे प्रदेश से 51 हजार दीपक इकट्ठे किए गए थे। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब अयोध्या में 25 से 30 लाख दीपक एक साथ प्रज्ज्वलित किए जाते हैं। ये सभी दीपक स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं। उन्होंने इसे स्थानीय कारीगरों के सशक्तिकरण का प्रतीक बताया।

यूपी के डिप्टी ...

हमारे वकीलों ने सारे प्रमाण दिखा दिए कि वो बच्चे उसी के पास थे, हमारे पास नहीं थे। इसका मतलब है कि अगर बच्चों के साथ कुछ हुआ है तो बच्चे जिसके साथ थे, उसी ने किया होगा। शिकायतकर्ता जांच के घेरे में अपने आप आ जाएगा। इसको ये बताना पड़ेगा कि इन बच्चों का हमसे संपर्क कहां हुआ। जब बच्चे हमारे पास आए ही नहीं को कैसे हम कुकर्म कर सकते हैं। बुधवार सुबह भी शंकराचार्य ने मीडिया से बात की थी। उन्होंने कहा, हिंदुत्व खतरे में है। जब केवल ड्रेस पहनकर लोग खुद को हिंदू बताने लगेंगे और बार-बार हिंदू-हिंदू कहेंगे, तो हिंदू को खतरा होना स्वाभाविक है। हिंदुत्व को हिंदुओं के बीच घुस आए ऐसे लोगों से खतरा है, जो वास्तव में हिंदू नहीं हैं। दिखावे के लिए खुद को हिंदू बताते हैं। उन्होंने कहा- एक-डेढ़ महीने से कहा जा रहा है कि और भी छात्रों का यौन शोषण हुआ है।

इंडिगो फ्लाइट में ...

और उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में दावा किया गया कि यात्री 4 घंटे से अधिक समय तक विमान में बिना वेंटिलेशन और खाना के बैठे रहे। यात्रियों ने यह भी दावा किया कि फ्लाइट पहले तकनीकी खराबी के कारण लेट हुई। इसके बाद ड्यूटी टाइम खत्म होने का हवाला देते हुए पायलट भी विमान से उतर गया। दूसरा पायलट लगभग 11 बजे पहुंचा। इसके बाद दोपहर में विमान ने उड़ान भरी। इंडिगो के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि फ्लाइट एक छोटी तकनीकी खराबी के कारण बे (पार्किंग) पर लौट आई थी। जांच और रखरखाव के दौरान कॉकपिट क्रू का ड्यूटी टाइम लिमिट पार हो गया, जिससे क्रू बदलना पड़ा और उड़ान में और देरी हुई।

उत्पीड़न का आरोप लगा महिला स्टाफ ने दिया इस्तीफा

कुलपति ने विशाखा चेयरमैन को भेजी शिकायत

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। KGMU के HRF (हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड) विभाग में तैनात एक महिला कर्मचारी ने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। पीड़िता ने मामले की शिकायत संस्थान प्रशासन से की है। कुलपति ने मामले की जांच के लिए विशाखा कमेटी को पत्र लिखा है। पीड़िता की ओर से 20 फरवरी को शिकायत पत्र के माध्यम से उत्पीड़न, छुट्टी से इनकार, गर्भावस्था के दौरान असंवेदनशील व्यवहार और बुनियादी सुविधाओं से वंचित किए जाने जैसे आरोप लगाए हैं। उन्होंने इन परिस्थितियों को अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का प्रमुख कारण बताया है। शिकायत में कहा गया है कि सेवा अवधि के दौरान, गर्भवती होने के बावजूद उन्हें कोई विशेष सहयोग या सुविधा प्रदान नहीं की गई। पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध होने के बाद भी उन पर अप्रत्यक्ष दबाव डाला गया और

टिप्पणियां की गईं, जिससे मानसिक तनाव की स्थिति बनी रही। आरोप लगाया कि पारिवारिक शोक जैसी आपात स्थिति में अवकाश का अनुरोध करने पर भी उन्हें सहानुभूति या समर्थन नहीं मिला। KGMU के मीडिया सेल प्रभारी डॉ.केके सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही कुलपति की तरफ से इस प्रकरण को विशाखा कमेटी के चेयरमैन को भेजा गया हैं। वो खुद इस पर निर्णय लेंगी कि इस विषय की जांच विशाखा कमेटी की परिधि में हैं।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकिाशत लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676